

जाट सभा ने यूपीएससी-आईएफएस में चयनित 53 प्रतिभाओं का किया सम्मान

■ शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, शिक्षा से बदलती है समाज की तस्वीर ■ कैटन अभिमन्यु ने सम्मान कार्यक्रम के लिए दिए 5 लाख रुपये

हरिभूमि न्यूज▶▶रोहतक

जाट सभा रोहतक की ओर से शुक्रवार को सेक्टर-1 स्थित जाट भवन में सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा परीक्षा-2025 में चयनित जाट समाज की प्रतिभाओं के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चयनित युवाओं सहित कुल 53 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार करना रहा। समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज



की तकदीर और तस्वीर बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। जाट समाज के युवाओं ने यूपीएससी और भारतीय वन सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर यह साबित किया है

कि वे अब केवल खेती, खेल और सेना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रशासनिक नेतृत्व और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं।

युवाओं की सफलता में परिवारों के संघर्ष का बड़ा योगदान : कैटन

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैटन अभिमन्यु ने कहा कि चयनित युवाओं की सफलता के पीछे उनके परिवारों का संघर्ष और त्याग छिपा है। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान से जुड़ी हुई है। उन्होंने युवाओं से प्रशासनिक पदों को जिम्मेदारी और सेवा का माध्यम मानने की अपील की। कैटन अभिमन्यु ने कहा कि यूपीएससी देश की सबसे प्रतिष्ठित और निष्पक्ष परीक्षा है, जहां सफलता केवल मेहनत और प्रतिभा के दम पर मिलती है। उन्होंने जाट सभा के प्रयासों की सराहना करते हुए ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रमों के लिए अपनी ओर से पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की।

प्रशस्ति पत्र, शॉल व स्मृति चिह्न जैद करिया

जाट सभा के प्रधान जखीर दूल ने बताया कि संस्था हर वर्ष इस प्रकार के सम्मान समारोह आयोजित करती है। इस बार चयनित सभी अभ्यर्थियों को 11-11 हजार रुपये की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र, शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। समारोह में विकास कुरु, दिव्या गहलोट, प्रज्ञा गुलिया, सिद्धार्थ सिंह, अभिमन्यु बालियां, दिशा धनखड़ और मानसी डागर सहित कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविद व अभिभावक मौजूद रहे।

ईवी और ऑटो उद्योग को नई रफ्तार देगा हरियाणा : नायब

■ मुख्यमंत्री ने हरियाणा भवन में उद्योग प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ बैठक की

हरिभूमि ब्यूरो▶▶नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य को लेकर नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा के औद्योगिक विकास, निवेश संभावनाओं और एकीकृत ईवी एवं ऑटोमोटिव विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान वैश्विक ईवी निर्माता कंपनी विनफास्ट से संबंधित प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विनफास्ट की कार चलाकर भी देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार निवेशकों को पारदर्शी नीतियां, बेहतर कानून व्यवस्था, कुशल



मानव संसाधन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर से निकटता, मजबूत राष्ट्रीय राजमार्ग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हरियाणा को ऑटोमोबाइल और ईवी उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर के माध्यम से निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी आवश्यक अनुमतियां और सेवाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूती मिली है।

जापानी उद्योगपतियों को दिया निवेश का न्योता



हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापानी निवेशकों को हरियाणा में निवेश और औद्योगिक साझेदारी का निर्माण देते हुए कहा कि भारत और जापान के संबंध विश्वास, अनुशासन, सौहार्द और उत्कृष्टता के खाड़ा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर मजबूत और लचीली सप्लाई चेन विकसित कर सकते हैं, जिससे स्मार्ट और ग्रीन भविष्य का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडो-जापान कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आज भारत में जापानी उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां करीब 394 जापानी उद्योग और 600 से अधिक जापानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जापान यात्रा के दौरान भी प्रतिष्ठित जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा जताई थी। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस : मुख्य सचिव

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार भविष्य की अर्थव्यवस्था और बदलती औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य में आधुनिक, तकनीक आधारित और उद्योग उन्मुखी कोशल विकास प्रणाली तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्रीन टेक्नोलॉजी, एडवांस मैनुफैक्चरिंग, डिजिटल रिकलिंग और उद्योग आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में बड़े सुधार लागू करने की तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शनिवार को कोशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य के रिकलिंग इकोसिस्टम में किंग जा रहे व्यापक सुधारों की समीक्षा की। इस मौके पर अधिकारी मौजूद रहे।

सेवा का अधिकार आयोग एप लॉन्च

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने साल 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए नया ऑटो अपील सिस्टम व्हाट्सएप चैटबूट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब लोग घर बैठे मोबाइल से ही सरकारी सेवाओं की जानकारी ले सकते और अपील भी कर सकते हैं। अब अगर किसी सरकारी सेवा में देरी होती है, तो लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने की आवश्यकता है। लोग व्हाट्सएप नंबर 6239466937 पर मैसेज भेजकर सेवा की जानकारी ले सकते हैं।

सीपीए सम्मेलन की तैयारी जोरों पर

चंडीगढ़। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के उत्तर भारत क्षेत्र के जोन-2 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हरियाणा विधान सभा सचिवालय में बैठकों का दौरा जारी है। इस सिलसिले में विस अध्यक्ष हरविन्द कल्याण ने लोक सभा सचिवालय में निदेशक डॉ. यमनम अरुण कुमार, हरियाणा पुलिस के महानिदेशक अजय सिंघल व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों की।

हरियाणा हरिभूमि 2

हरियाणा हरिभूमि 2

■ शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, शिक्षा से बदलती है समाज की तस्वीर ■ कैटन अभिमन्यु ने सम्मान कार्यक्रम के लिए दिए 5 लाख रुपये

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैटन अभिमन्यु ने कहा कि चयनित युवाओं की सफलता के पीछे उनके परिवारों का संघर्ष और त्याग छिपा है। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान से जुड़ी हुई है। उन्होंने युवाओं से प्रशासनिक पदों को जिम्मेदारी और सेवा का माध्यम मानने की अपील की। कैटन अभिमन्यु ने कहा कि यूपीएससी देश की सबसे प्रतिष्ठित और निष्पक्ष परीक्षा है, जहां सफलता केवल मेहनत और प्रतिभा के दम पर मिलती है। उन्होंने जाट सभा के प्रयासों की सराहना करते हुए ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रमों के लिए अपनी ओर से पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की।

कर्मचारियों की एसीआर होगी डिजिटल : रस्तोगी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत अब कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और जिला प्रशासन को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में अनुसार अप्रैल 2027 से मैनुअल

■ कर्मचारियों का मूल्यांकन डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम से होगा

एसीआर प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी और सभी मूल्यांकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होंगे। यह प्रणाली एचआरएमएस पोर्टल से जुड़ी होगी, जिससे कर्मचारियों के कार्यों का वास्तविक समय में आकलन संभव हो सकेगा। सरकार ने सभी विभागों से लंबित एसीआर की सूची भी मांगी है ताकि प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जा सके। नई व्यवस्था के तहत ऑनर बोर्ड पर कर्मचारियों की प्रदर्शन आधारित रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी।

प्रदेश के 17 जिलों में बिजली संकट : हुड़ा

चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में भीषण गर्मी के कारण प्रदेश का बिजली इंडास्ट्रियल हाफने लगा है। राज्य के 17 जिलों की गाउंड रिपोर्ट बताती है कि शहर और ग्रामीण इलाकों में हर दिन 3 से 14 घंटे तक के अघोषित बिजली कट लग रहे हैं। हालत यह है कि ट्रान्सफार्मर ओवरलोड होकर जल रहे हैं। केबलों में आग लग रही है। प्रभूज उड़ने की हजारों शिकायतें रोज केंद्रीय रूम पहुंच रही हैं। सरकार की 'जगमगा योजना' वाले दावों के बीच गांवों में सिर्फ 10 से 12 घंटे बिजली मिल पा रही है, जिससे पेपजल और खेती की सिंचाई का संकट भी खड़ा हो गया है। हुड्डा ने कहा कि गर्मी का मौसम आते ही एकबार फिर बीजपी सरकार के दावे हवा में उड़ने लगे और बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। पूरे प्रदेश में लोग कई-कई घंटों के पावर कट झेल रहे हैं।

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुख्यांक के द्वारा निम्न कृषि भूमि का बैयनामा प्रस्तावित है :-
5834
मनकि फूलपुरी विषया हानसिंह पुत्र टेकचन्द, निवासी एवं बिस्वेदार गांव बादली, तहसील बादली, जिला झज्जर (हरियाणा) में अराजी बन्धे इन्द्राज जगनबन्दी वर्ष 2023-24, के अनुसार खेत नं 3022 /2587 मिन्. खाता नं 3379, मुग नं 286, किला नं 1(8-0), 2 /1(2-8), 10 /1(3-7), मुग नं 287, किला नं 5(9-12), 6 /1 /1(2-13), किते 5, तादादी रकबा 24 कनाल 0 मरला का 1 /9 भाग, बकरूर 2 कनाल 13.33 मरले (0.3333125 एकड़), बाका रकबा मौजा बादली, तहसील बादली, जिला झज्जर की मालिक व काबिज है जिसको बेव किया जा रहा है। जिसका कब्जा मुग नं 287, किला नं 6 /1 /1(2-13) किता 1, तादादी रकबा 2 कनाल 13 मरले (0.33125 एकड़) पर दिया जा रहा है।
यदि कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त भूमि में मुखलफाना हक, स्वामित्व, कब्जा या अन्य कोई सम्बन्ध रखता है या किसी को इस बंध पर कोई रेटारज है तो वह व्यक्ति उपरोक्त भूमि में अपने हक, दावे सम्बन्धी जरूरी दस्तावेजों व साक्ष्य सहित इस विज्ञापि के प्रकाशित होने के 14 दिन के अन्दर अघोहस्ताक्षरित से सम्पर्क करे या भेजे, अन्यथा यह माना जायेगा कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त भूमि में कोई दावा, हक, स्वामित्व, कब्जा या किसी प्रकार का अन्य कोई सम्बन्ध नहीं रखता और मेरा मुख्यांक उक्त अराजी के बंध से सम्बन्धित अग्रिम सभी कार्यवाही करेगा।
सर्वसाधारण को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुख्यांक के द्वारा निम्न कृषि भूमि का तबादलानामा प्रस्तावित है :-
SW/BSO/750
मनकि राकेश पुत्र रामकिशन पुत्र गीना, निवासी एवं बिस्वेदार गांव ईसाइलपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर (हरियाणा) में अराजी बन्धे इन्द्राज जगनबन्दी वर्ष 2021-22, के अनुसार अराजी खेत नं 23 /12, खाता नं 25, मुग नं 11, किला नं 25(6-4), मुग नं 12, किला नं 21(8-0), मुग नं 14, किला नं 1(8-0), 2(8-0), मुग नं 15, किला नं 5(8-16), किते 5, तादादी रकबा 39 कनाल 0 मरला का 1 /19 भाग, बडवदर 2 कनाल 1.05 मरला (0.2566525 एकड़) बाका रकबा मौजा ईसाइलपुर, तहसील बादली, जिला झज्जर का मालिक व काबिज है जिसका सबादना प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुख्यांक के साक्ष किया जा रहा है तथा प्रथम पक्ष द्वारा मेरे मुख्यांक को मुग नं 10 14, किला नं 2 मिग पूर्व (2-1), किता 1, तादादी रकबा 2 कनाल 1 मरला (0.25625 एकड़) पर कब्जा दिया जा रहा है।
अतः यदि कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त भूमि में मुखलफाना हक, स्वामित्व, कब्जा या अन्य कोई सम्बन्ध रखता है या किसी को इस तबादलानामा पर कोई रेटारज है तो वह व्यक्ति उपरोक्ता भूमि में अपने हक, दावे सम्बन्धी जरूरी दस्तावेजों व साक्ष्य सहित इस विज्ञापि के प्रकाशित होने के 14 दिन के अन्दर अघोहस्ताक्षरित से सम्पर्क करे या भेजे, अन्यथा यह माना जायेगा कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त भूमि में कोई दावा, हक, स्वामित्व, कब्जा या किसी प्रकार का अन्य कोई सम्बन्ध नहीं रखता और मेरा मुख्यांक उक्त अराजी के तबादले से सम्बन्धित अग्रिम सभी कार्यवाही करेगा।
दिनांक : 22.05.2026
विनय कुमार सैनी एडवोकेट, छिंटोय लाल, मग नं 285, सक्टर-14, गुरुग्राम - 122001 Mobile : 9810203697 E-mail : svkggn@yahoo.com

बैंक घोटाले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है सीबीआई

योगेंद्र शर्मा▶▶चंडीगढ़

हरियाणा के दर्जनभर से अधिक विभागों के सरकारी धन की बंदरबांट और गड़बड़ी में शामिल आरोपियों के मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, लेकिन मामले में आगे अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल होने की प्रबल संभावना है। करोड़ों रुपये के इस घोटाले में दो अधिकारियों को गवाह के तौर पर शामिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार, अब तक जिन आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके अलावा भी दो अन्य आईएएस अधिकारियों के खिलाफ धारा 17-ए के तहत अनुमति दिए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। मामले की जांच अभी जारी है और कई और अहम खुलासे होने

की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में विभिन्न विभागों के सरकारी फंड में 500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित हेराफेरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली चार्जशीट पंचकुला स्थित विशेष अदालत में दाखिल कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 15 आरोपियों की नामजद किया है, जिनमें बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, शेल कंपनियां के संचालक और निजी व्यक्ति शामिल हैं। आरोपियों पर साजिश रचने, धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, बैंक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से विभिन्न विभागों के खातों से अवैध रूप से बड़ी राशि निकाली गई।

एचपीजीसीएल में वित्तीय नियमों को लेकर सख्ती

चंडीगढ़। पांच लौ करोड़ से अधिक के बैंक घोटाले के बाद हरियाणा सरकार ने वित्तीय अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब सभी सरकारी बोर्डों और निगमों में वित्त विभाग के निदेश बिना किसी अतिरिक्त अनुमोदन के अनिवार्य रूप से लागू होंगे। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) ने भी वित्तीय नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार किसी भी वित्तीय कार्य के लिए वित्त विभाग की गाइडलाइन सर्वोच्च मानी जाएगी और सभी निर्णयों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हाल ही में सामने आए एफडी घोटाले और निरपत्ताकारियों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

पं. भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आधुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक
इस संस्थान के विभिन्न विभागों में केवल छह माह की अवधि हेतु अर्थात् सत्र 01.07.2026 से 31.12.2026 हेतु हरियाणा सरकार के अनुमोदन के अनुरूप 7वें सीपीसी के अनुसार एफपीएल-10 में रु. 56100 + डीए के पारिश्रमिक सहित सीनियर / जूनियर हाउस सर्जन के 153 रिक्त पदों को भरने के लिये पात्र चिकित्सा स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। संभाव्य उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी हेतु रु. 500/- और हरियाणा निवासी के एससी / बीसी इत्यादि हेतु रु. 125/- की दर से निदेशक (लेखा शाखा) के कार्यालय के काउंटर से प्राय निधारित प्रारूप पर आवेदन करना चाहिए।
सम्पर्क टेलीफोन नंबर सहित सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण आवेदन अधोहरताक्षरी के कार्यालय में 05.06.2026 तक ठीक अप. 5.00 बजे तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए। अधिक विस्तृत शर्तों और पात्रता हेतु हमारे संस्थान की वेबसाइट www.uhsr.ac.in और www.pgimsrohtak.ac.in देखें।
हता/- चिकित्सा अधीक्षक
संवाद-1241/11/85/2027/45482/सी/88/6 दि. 22.05.26

DISTRICT RED CROSS SOCIETY, ROHTAK

NOTICE INVITING OPEN TENDER

The Worthy Deputy Commissioner -cum- President, District Red Cross Society, Rohtak under open bid system for the following work/item invite open tender:-

Sr. No.	Name of work and file reference.	EMD/Bid Money to be deposited.	Base price of the bid.	Reserve license fee for one year.
1.	Allotment of shop No. 07 Chemist in Shopping Complex in UHS, Rohtak for one year extendable for another two years on yearly basis subject to satisfactory report with the condition that license fee of the said shop will be increased by 10% of the license fee per year.	Rs. 40,000/- (Rs. Forty thousand only)	The open bid will start from Rs. 8,50,000/- (Rs. Eight lakh fifty thousand only)	Rs. 1,02,000/- (Rs. One Crore two lakhs only) for one year + GST extra as applicable.

1- The bidder shall deposit 40,000/- (Rs. Forty thousand only Earnest Money Deposit (EMD) (refundable) in account of Indian Red Cross Society, District Branch, Rohtak Account No. 000234022000022 IFSC Code: UTIBINR0801 or in form of cash deposited in office before closing date (08-06-2026) upto 10:00 am. Non submission of EMD would lead to rejection of the tender.

2- Open bid of tender will start on 08-06-2026 at 11:00 AM. In the Conference Hall of Vikas Bhawan o/o Addl. Deputy Commissioner, Rohtak under the supervision of competent authority to be appointed by the Deputy Commissioner -cum- President, District Red Cross Society, Rohtak.

3- The open bid will start from WorthRs. 8,50,000/- (Eight Lakhs fifty thousand) only.

4- Terms and conditions on each aspect as specified in the tender document available at the web site of District Red Cross Society, Rohtak i.e. <http://redcrossrohtak.org/> should only be followed or the same can be obtained from the office of Secretary, District Red Cross Society, Rohtak from in any working day in working hours only.

5- It is clarified that only hard copy of the bid document/supporting documents such as earnest money deposit receipt of the concerned bank shall be accepted. Only the documents which have been attached with tender documents shall be considered. If any documents found missing from the tender, it will be the responsibility of bidder.

6- Tenders should be placed by the licensee in the sealed box which will be kept under the supervision of Secretary, District Red Cross Society, Rohtak in his office i.e. Red Cross Bhawan-II near Tehsil Office, Rohtak.

7- For more information, please contact Secretary, District Red Cross Society, Rohtak Mobile No. 9812469292. e office land Line Phone No. 01262- 254588.

Secretary, District Red Cross, Rohtak.

उत्तर रेलवे

ई-निविदा

खुली निविदा संख्या 10-अम्बाला/2026-27 दिनांक 21.05.2026

वरिष्ठ मंडल अभियान्त-समन्वय/अम्बाला के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-निविदा के माध्यम से इच्छुक ठेकेदारों से निम्नालिखित कार्यों हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो कि उन कार्यों के सामने दी गयी तिथि को 15.00 बजे तक खुली रहेगी और उससे बाद खोली जाएगी।

1 कार्य का नाम: रामपुरा फूल रेलवे स्टेशन, गिददबहाबा रेलवे स्टेशन और मलोट रेलवे स्टेशन पर मौजूदा FOB के लिए रैप्य की व्यवस्था।			
अनुमानित लागत (रु.) अग्रिम राशि (रु.) कार्य समाप्ति का समय निविदा खुलने की तिथि			
3,42,24,529	6,84,500	12 महीने	16.06.2026
2 कार्य का नाम: अंबाला डिवीजन में एलडीएच-बीजूआई स्टेशन पर एलसी संख्या सी-29, सी-52 और बीटीआई-एसजीएसआर सेक्टर पर एलसी संख्या 48 के शेड इंटर्लॉक लेवल क्रॉसिंग गेटों पर आईवीएस (IPS) लगाने का प्राक्खान। (केवल सिविल कार्य)			
अनुमानित लागत (रु.) अग्रिम राशि (रु.) कार्य समाप्ति का समय निविदा खुलने की तिथि			
53,55,974	1,07,100	08 महीने	10.06.2026
3 कार्य का नाम: यमुनानगर जमाखरी रेलवे स्टेशन याई में SSE/PI-Way/YJUD के संरक्षण में ADEN/SRE के अंतर्गत लाइन संख्या 2 एवं 3 (पैसेंजर लूप लाइन) पर 60 किग्रा (90 UTS) रेलों को PSC वाइबर स्लीपर 1660 संख्या/किमी (LW/R) सहित बिछाकर 1.718 टीकेएम का CTR(P), लाइन संख्या 5 पर 60 किग्रा रेलों को PSC स्लीपर 1540 संख्या/किमी सहित 0.919 टीकेएम का CTR(SM), चॉदपुर साइडिंग में 52 किग्रा रेलों सहित TRR(S) (LW/R) तथा याई सुधार कार्य जैसे मलबा निरालाकरण, डीप खोर्गिंग, सैंड बंध आदि का कार्य।			
अनुमानित लागत (रु.) अग्रिम राशि (रु.) कार्य समाप्ति का समय निविदा खुलने की तिथि			
98,59,716	1,97,200	12 महीने	10.06.2026
4 कार्य का नाम: ADEN/SRE के अंतर्गत SSW, MFB और PKY याई में PSC वाइबर स्लीपर पर बिछाई गई 60kg (90 UTS) रेलों के साथ लूप लाइनों का CTR(P) 1660 नग/किमी (LW/R) और HNC-SRE (UP लाइन) के बीच 60kg 90 UTS रेलों के साथ 1.6 किमी TRR(P) का कार्य, तथा PKY, KWT, HNC, JUDW, MFB और DZP याई में याई सुधार कार्य जैसे CTR, TRR, TTR, TTR डीप खोर्गिंग, सैंड बंध, मलबा का निपटान आदि।			
अनुमानित लागत (रु.) अग्रिम राशि (रु.) कार्य समाप्ति का समय निविदा खुलने की तिथि			
1,80,19,239	3,60,400	12 महीने	10.06.2026
5 कार्य का नाम: ADEN/Shimla के अंतर्गत यात्री लूप लाइनों पर सी.एस.सी. वाइडर स्लीपरी पर बिछाई गई 60 किलोग्राम (90 यूटी.एस) रेलों के साथ सी.टी.आर. (पी), 1660 नग/किमी., टी.टी.आर. तथा याई सुधार कार्य जैसे की टी.एफ.आर., पी.आर.सी. स्लीपरी और रेलों का आकारमिक नवीनीकरण तथा कालका याई की डीप खोर्गिंग।			
अनुमानित लागत (रु.) अग्रिम राशि (रु.) कार्य समाप्ति का समय निविदा खुलने की तिथि			
81,90,979	1,63,800	12 महीने	10.06.2026
6 कार्य का नाम: ADEN/SRE के अंतर्गत क्षेत्र में आने वाले PKY, KWT, HNC, YJUD, JUDW, MFB और DZP याई के सुधार कार्यों के साथ-साथ याई जंक्शन निकारी में सुधार।			
अनुमानित लागत (रु.) अग्रिम राशि (रु.) कार्य समाप्ति का समय निविदा खुलने की तिथि			
3,44,34,313	6,88,700	12 महीने	10.06.2026
7 कार्य का नाम: तंदवाल (हॉल्ट) रेलवे स्टेशन पर रैप के साथ 03 मीटर चौड़ी एकओबी की व्यवस्था।			
अनुमानित लागत (रु.) अग्रिम राशि (रु.) कार्य समाप्ति का समय निविदा खुलने की तिथि			
2,38,09,856	4,76,200	12 महीने	10.06.2026
8 कार्य का नाम: बराड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्री प्लेटफार्म को निचले स्तर से उच्च स्तर तक 600 मीटर तक ऊंचा करना और उसका विस्तार करना।			
अनुमानित लागत (रु.) अग्रिम राशि (रु.) कार्य समाप्ति का समय निविदा खुलने की तिथि			
3,18,13,818	6,36,300	12 महीने	10.06.2026
9 कार्य का नाम: अंबाला कैंट, लालरू, घुलकोट, धग्गार और धग्घर स्टेशनों के प्लेटफार्म पर टेराकोट गार्डिंग एवं वॉरिंग टाइल्स का प्रयाजन।			
अनुमानित लागत (रु.) अग्रिम राशि (रु.) कार्य समाप्ति का समय निविदा खुलने की तिथि			
67,64,124	1,35,300	08 महीने	10.06.2026

नोट:- 1. ठेकेदार को शर्तों के अनुसार निविदा योग्यता पूरी करने हेतु सभी जरूरी सम्बंधित डॉक्यूमेंटों के कॉपीकरण को भी रेलवे वेबसाइट IREPS पर अपलोड करनी जरूरी है। 2. अग्रिम राशि ऑन लाइन पेमेंट नोट बैंकिंग/ऑन पेमेंट/बैंक जारी वांच अनुसार IV के द्वारा ही स्वीकार्य है। 3. निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु रेलवे वेबसाइट www.ireps.gov.in पर लोग ऑन करें। 4. ठेकेदार को ई-निविदा में भागदारी हेतु (क्वालिफाइड डिजिटल सिग्नेचर सॉफ्टवेयर के द्वारा लोग ऑन करना होगा। 5. जी. एस. टी. एक्ट 2017 के अनुसार लागू होगी।

1720/2026

नोट:- 1. ठेकेदार को शर्तों के अनुसार निविदा योग्यता पूरी करने हेतु सभी जरूरी सम्बंधित डॉक्यूमेंटों के स्कैनिंग कोपी को रेलवे वेबसाइट IREPS पर अपलोड करनी जरूरी है। 2. अग्रिम राशि ऑन लाइन पेमेंट गेट बैंकिंग/नेट बैंकिंग/बैंक गारंटी बांड अनुबंध IV के द्वारा ही स्वीकार्य होंगे। 3. निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु रेलवे वेबसाइट www.ireps.gov.in पर लोग ऑन करें। 4. ठेकेदार को ई-निविदा में भागीदारी हेतु (क्लास-III) डिजिटल सिग्नेचर सॉर्टिफिकेट द्वारा लोग ऑन करना होगा। 5. जी. एच. ए.टी. एक्ट 2017 के अनुसार लागू होगी।

1720/2026

शाहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

हरियाणा सरकार	निविदा सूचना	
क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम
1	लॉनिवि भ व प अंबाला	अंबाला जिले में अंबाला सिटी में राजकीय पशु चिकित्सालय का निर्माण + 12 कार्य।
2	लॉनिवि भ व प गुरुग्राम	गुरुग्राम में लॉनिवि विश्राम गृह में मानवाधिकार आयोग कार्यालय में 4 अदद कार्यालयों और वॉशरूम का पुनरीक्षार समेत वॉल पैन्लिंग और अन्य सहायक कार्य।
3	पंचायती राज भिवानी	गांव टिगराजा जीपी में 5 अदद खेत खलियान रास्ता आईपीवी की पेवमेंट (सीएम घोषणा 24219)।
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा भिवानी	सिवानी जल सेवाएं यांत्रिकी उपमंडल तोताम में सिवानी कैनाल की 10 अदद 150 एचपी मोटरस की रिवाइडिंग।
5	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा सिरसा	आरडी 0 से 13950 टेल तक लोहारू लिंक चैनल की क्षतिग्रस्त पैच लाइनिंग की मरम्मत + 3 कार्य।
6	कृषि एवं किसान कल्याण रोहतक	गांवों

ह	ल	व	ल	टा	द	वा	ख	ना	
दय	व	व						र	ज
ज			कु	यु	म	त		नी	
ब	द	मा	स	ले	ना		सो	त	न
र		हि		फ	ल	प्रा		ज	
न	उ	र	वा	सी	ज	ण	ना	य	क
	र		द		मा	ली	पा		ल
अ	ल	ज		म	न		वौ	की	दा
प			चि	सि	रा	की			
स	ज		क	न	क			गे	
घ	इ	क	न	ता	डै	मा	ला	गु	

हरियाणा लोक सेवा आयोग

बेज नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला

घोषणा

विषय : उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा में पर्यावरणीय विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा (विज्ञा. सं. 49/2024)

नीचे वर्णित पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा हेतु क्वालीफाइड हो चुके उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी के लिए एतद द्वारा यह घोषणा की जाती है कि आयोग ने नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुरूप विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है :-

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	विज्ञा. सं.	परीक्षा की तिथि व समय
1.	उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा में पर्यावरणीय विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर (कॉलेज कैडर)	49/2024	06.06.2026 पूर्वा. 10:00 बजे से अप. 1:00 बजे तक

उम्मीदवारों को अपने प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट अर्थात <https://hpsc.gov.in> पर उपलब्ध करवाए गए लिंक से 01.06.2026 से डाउनलोड करने का परामर्श दिया जाता है।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी उम्मीदवार जो उपरोक्त पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा हेतु क्वालीफाइड हो चुके हैं, को परीक्षा में बैठने के लिए अंतिम रूप से अनुमति दी जा रही है, जो विज्ञापन के अनुरूप सभी पात्रता शर्तें पूर्ण करने के अधीन है।

टिप्पणियाँ :-

- उम्मीदवारों को प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने और ए-4 साइज पेपर पर इसका प्रिंट लेने का निर्देश दिया जाता है ताकि उनके फोटो और अन्य विवरण आसानी से देखे / प्रमाणित किये जा सकें। अस्पष्ट फोटो / हस्ताक्षरों सहित छोटे आकार के प्रवेश-पत्र वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायगी।
- उम्मीदवारों को प्रवेश-पत्र पर दिये गये सभी निर्देश बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का परामर्श दिया जाता है।

दिनांक : 21.05.2026
 संवाद- 1156/13/382/2027/45481/88/6 दि. 22.05.26

हस्ता/- उप सचिव
हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला

(भारत सरकार का उपक्रम / a Govt. of India Undertaking) मुख्य परिचालन अधिकारी (मु०परि०अधि०) की भर्ती	
आई०पी०बी०बी०, मुख्य परिचालन अधिकारी (मु०परि०अधि०) के पद के लिए योग्य, ऊर्जावान और गतिशील उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जैसा कि नीचे दिए गए विज्ञापन में विस्तृत किया गया है।	
संक्षिप्त विवरण :	
पद की प्रकृति :	सविदात्मक
श्रेणी :	अनारक्षित
कार्यकाल :	प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए होगा तथा बैंक द्वारा इसे दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
आयु सीमा :	आयु 40 वर्ष से कम और 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता :	भारत सरकार या उसके नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ पूर्णकालिक नियमित स्नातक या उसके समकक्ष योग्यता
कार्य अनुभव :	बैंकों या वित्तीय संस्थानों में कम से कम 18 वर्षों का अनुभव। इसमें से, न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव विशेष रूप से किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के परिचालन या व्यावसायिक प्रक्रियाओं को संचालन में होना चाहिए। उसके अतिरिक्त, पिछले पाँच वर्षों के भीतर, उम्मीदवार ने किसी सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अधिकतम दो स्तर नीचे के पद पर कम से कम दो वर्ष तक कार्य किया हो।

पिस्तुत विज्ञापन हेतु, कृपया बैंक को आधिकारिक वेबसाइट <https://ipbbonline.bank.in/web/ipbb/current-openings> पर जाएं।
स्थान : नई दिल्ली **ह./-**
CBC-06346/12/0002/2627 **उप-महाप्रबंधक (मांसो)**

नवेवाले-4
ने
-3,3
का वारिस-6
-2
भा भाव-4
वा-3
अंग्रेजी में-3)
-2

25.जीवन निर्वाह का
हंग,-3,3
27.विजयादशमी-4
28.मोड़, छोर-2
29.मृत्यु का देवता,
यम-4
31.बुरी आदत-3
32.सभ्य व्यवहार-3
34.मार्ग-2
36.गोंद, वार्निश-2

शब्द पहेली- 6233 का हल

ह	ल	व	ल	दा	द	वा	खा	ना
क्ष्य		व	ल	क	वा		र	ज
ज		कु	सु	म	त		नी	
ब	द	मा	श	दो	ना	खी	त	व
र	हि	फ	ल	ग्रा		न		
न	ज	र	वा	सी	ग	ण	ना	य
	र	द	मा	ली	पा	ल		
अ	ल	ज		म	न	खी	की	दा
प		रि	सि	स	की			व
श	ज	क	न	क	दा		गे	
घ	इ	क	न	ता	ये	मा	लव	जू

अब पाकिस्तान में 'काँकरोच अवामी पार्टी' कई अलग-अलग वर्जन बने, ज्यादा मीम कल्चर व ऑनलाइन व्यंग्य तक सीमित

एजेंसी ►► कराची/नई दिल्ली

भारत में वायरल हुई 'काँकरोच जनता पार्टी' अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है। भारतीय सोशल मीडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर वहां 'काँकरोच अवामी पार्टी' और 'काँकरोच अवामी लीग' जैसे पेज सामने आए हैं।

- इंस्टाग्राम पेज पर भारतीय आंदोलन से प्रेरित माना
- लिखा हों कांपी किया किसे फर्क पड़ता है

►► पाकिस्तानी वर्जन का क्या इरादा है ?

पाकिस्तानी काँकरोच पेज खुद को वहां की जेन-जी पीढ़ी का आवाज बता रहे हैं। इनका दावा है कि वे पाकिस्तान की पारंपरिक राजनीति के विकल्प के तौर पर सामने आना चाहते हैं। कई पोस्ट्स में पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाफ (पीटीआई), पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) जैसी मुख्यधारा की पार्टियों पर तंज कसा गया है। एक एक्स अकाउंट @CockroachAP ने उर्दू में लिखा, जिन्हें सिस्टम ने काँकरोच समझा, हम उन्हीं अवाम का आवाज हैं। वहीं Cockroach Awami League Pakistan नाम का दूसरा पेज हर हालात में जिंदा है जैसे स्लोगन के साथ खुद को युवाओं का प्रतीक बता रहा है। भारत की काँकरोच जनता पार्टी के पास संस्थापक, वेबसाइट और एक तरह का घोषणापत्र मौजूद है, लेकिन पाक में कई अलग-अलग वर्जन बन गए हैं। वहां ज्यादा मीम कल्चर व ऑनलाइन व्यंग्य तक सीमित दिख रहा है।

भारत में 'काँकरोच जनता पार्टी' यानी सीजेपी की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई। इसका आधार उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने कथित तौर पर बेरोजगार एक्टिविस्ट युवाओं की तुलना 'काँकरोच' और 'पैरासाइट' से की थी। हालांकि बाद में सफाई दी गई, लेकिन सोशल मीडिया में बयान पर

बहस छिड़ गई। यूएस में रहने वाले भारतीय मूल के पीआर ग्रेजुएट व आप के पूर्व सहयोगी अभिजीत दिपके ने 16 मई को सोशल मीडिया पर 'काँकरोच जनता पार्टी' कैपेन लॉन्च कर दी। उन्होंने खुद को मजाकिया अंदाज में 'काँकरोच' बताते हुए इस आंदोलन को बेरोजगार और सिस्टम से नाराज युवाओं की आवाज कहा।

आप का 'सीक्रेट प्रोजेक्ट' है काँकरोच जनता पार्टी

- पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। काँकरोच पार्टी विवादों में घिर गई है। अभियान को शुरू करने वाले अभिजीत और आम आदमी पार्टी के कनेक्शन को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी और अन्य कई लोगों ने काँकरोच पार्टी की राजनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। काँकरोच जनता पार्टी डिजिटल अभियान है, जिसे बॉस्टॉन में रह रहे अभिजीत दीपके ने शुरू किया है। दीपके पहले केजरीवाल की पार्टी की सोशल मीडिया और चुनावी कैपेन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। पार्टी के राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठने लगे हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह वास्तव में स्वतंत्र पार्टी है या ये आदमी पार्टी का एक प्रयोग है। लोग के मन में सवाल हैं कि क्या पदों के पीछे से आप की ओर से काँकरोच जनता पार्टी को कंट्रोल किया जा रहा है?

ग़ारने की मिल रही धमकी

काँकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दीपके ने सोशल मीडिया पर दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार को धमकी दी जा रही है। अभिजीत ने एक्स पर वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें एक युवक कथित तौर पर धमकी दे रहा है। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "क्या अधिकारी इन धमकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?"

अभिजीत दीपके पहली ऑनलाइन पिटीशन लेकर आए। इसमें उन्होंने नीट पेपर लोक मामले में शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।

पानीपत में काँकरोच जनता पार्टी के पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन

पानीपत। पानीपत की कचहरी में प्रेक्टिस करने वाले अभिवक्ता यानि एडवोकेट सुधीर जाखड़ ने काँकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सचिव को आवेदन पत्र भेजा गया है। यह आवेदन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत दिया गया है। वहीं, राष्ट्रीय संयोजक सुधीर जाखड़ ने जानकारी दी।

उप्र पुलिस ने समझाकर उतारा

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हथियागढ़ बाजार में शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे हड़कंप मच गया। रायपुर थाना छपिया की रेशमा (23) नामक युवती अपने प्रेमी के धोखे से परेशान होकर नंगे पांव मोबाइल टावर पर चढ़ गई है। युवती लगभग 20 फीट ऊपर बैठकर हंगामा करने लगी। सुबह निकले लोगों ने उसे देखा और तुरंत अन्य लोगों को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन

शादी का वादा करके मुंबई भागा प्रेमी प्रेमिका ने टावर पर चढ़ काटा बवाल



वह टावर पर बैठी रही। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद समझाकर नीचे उतारा।

ये है मामला

रेशमा की एक ही मांग थी कि उसके प्रेमी अमित (पुत्र लाला, निवासी गोदहना, थाना सादुल्लाह नगर, जिला बलरामपुर) को पुलिस पकड़कर लाए और उससे उसकी शादी करवाए। रेशमा ने बताया कि तीन साल पहले अमित और उसके परिजनों के बीच यह समझौता हुआ था कि 1 मई 2026 को तीन साल पूरे होने के बाद वे शादी करेंगे। इस समझौते के बाद अमित मुंबई चला गया। अब समझौते का समय पूरा होने के बावजूद वह रेशमा से शादी करने नहीं आ रहा है और न ही उसका फोन उठा रहा है। रेशमा ने इस संबंध में छपिया थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

बंगाल में ईडी का 9 जगह छापा

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर नए छापे मारे। ये छापे कोलकाता पुलिस के निरपत्तार अधिकारी शंतनु सिन्हा बिस्वास और कथित अपराधी बिस्वजीत पौद्धार उर्फ सोना पप्पू से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत मारे गए। उन्होंने बताया कि कोलकाता और मुर्शिदाबाद में कुल नौ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। इन जगहों में मोहम्मद अली उर्फ मैकस राजू, बिस्वास के भतीजे सौरव अधिकारी, बिस्वास के एक करीबी सहयोगी और कोलकाता पुलिस में सब-इंस्पेक्टर रहिल अमीन अली और मुर्शिदाबाद में बिस्वास के घर शामिल हैं।

10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 18 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनावों की घोषणा की। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए चुनाव 10 राज्यों में होंगे, जहां मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग-अलग तारीखों पर रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार-चार सीटों पर; मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन सीटों पर; झारखंड में दो सीटों पर; और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सीट पर होंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है।

वैश्विक शांति और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण क्षण

हरिद्वार। योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा के पथ-प्रदर्शक आचार्य बालकृष्ण को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज एक और प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया गया। मुंबई में आयोजित वैश्विक "बिलियनेयर्स फॉर पीस कॉन्वलेव 2026" में 'मैं शांतिदूत हूँ - वैपियन हेल्थ अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्व शांति, मानवता, स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक कल्याण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। आचार्य बालकृष्ण को यह सम्मान ऐसे समय में प्राप्त हुआ है जब आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया में अभूतपूर्व स्वीकार्यता मिल रही है। सम्मान प्राप्त करने के उपरान्त आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि एक स्वस्थ मानव ही शांतिपूर्ण समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं, अपितु सम्पूर्ण मानवता को संतुलित, निरोध और सकारात्मक जीवन की दिशा प्रदान करने वाला विज्ञान है। भारत सदैव 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का प्रतिनिधित्व करता आया है और आज पूरी दुनिया शांति, सहअस्तित्व और समग्र स्वास्थ्य के लिए भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है। आज विश्व जिस मानसिक तनाव, असंतुलित जीवनशैली और स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है, उसका समाधान प्रकृति और भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है।

युवाओं को आज मिलेगी बड़ी सौगात

पीएम मोदी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे



कई मंत्रालयों में मिलेगी नियुक्ति

रोजगार मेले के तहत चयनित उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग समेत कई सरकारी विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और संगठनों में भी युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी।

और से यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना प्रधानमंत्री की प्रमुख प्रतिबद्धताओं में शामिल है और रोजगार मेला उसी सोच की आगे बढ़ाने का माध्यम बन चुका है।

पंजाब: भाखड़ा नहर में 32 फीट की गहराई से निकला 26 साल पुराना राज, ड्रेस से खुलासा

कीरतपुर साहिब। पंजाब की भाखड़ा नहर में करीब 26 साल पहले गिरी एक मारुति ओमनी वैन को अब बरामद किया गया है। वर्ष 2000 में कीरतपुर साहिब क्षेत्र के गांव कोटला के चार लोगों को लेकर ये वैन नहर में समा गई थी। हादसे के बाद लंबे समय तक तलाश चली लेकिन न शव मिले थे और न वाहन। अब 32 फीट की गहराई से भाखड़ा ने ये राज उगला है। गांव कोटला में सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी कि आज से 26 साल पहले 20 अक्टूबर 2000 को नहर में गिरे लोगों का कभी पता भी चलेगा। इस वैन में कोटला में मिठाई की दुकान करने वाले मुनी लाल (36), तेजराम (37) वैन के ड्राइवर, किसान सुरजीत सिंह और उसका आठ साल का बेटा कालू सवार थे।

पेपर लीक रोकने एनटीए ने कसी कमर, 30 दिन चुनौती भरे, सोशल मीडिया पर भी रखेंगे नजर

एजेंसी ►► नई दिल्ली

गड़बड़ बन सकती है बड़ी मुसीबत

आगामी 21 जून को दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में एजेंसी जीरो ट्रस्ट नीति के तहत काम कर रही है। एजेंसी अब किसी भी स्तर पर सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पेपर लीक के बाद एनटीए अब कड़ी निगरानी, नियमित ऑडिट और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रहा है।



30 दिन के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित करना एक बड़ी चुनौती है। अगर समय की कमी से कोई भी छोटी सी गड़बड़ हुई, तो यह एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी गुस्सा देखा गया था। इसके बाद ही दोबारा परीक्षा करने का फैसला लिया गया। एजेंसी की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा कराना ही नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखना भी है। एनटीए का मानना है कि वे छात्रों को बार-बार निराश नहीं कर सकते।

गुरु गोरक्षनाथ स्मृति दिवस

के उपलक्ष्य में देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

23 मई, 2026

“ भारतीय संतों और ऋषियों की भूमिका केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही है। उन्होंने राष्ट्र और समाज के हर आयाम को सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया है। ”

- नरेन्द्र मोदी

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

www.prharyana.gov.in | Follow us on [social media icons] @dipharyana

चिंतन जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता जरूरी

देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी राज्यों तक सूरज आग उगल रहा है। हालात इतने भयावह हैं कि दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत के 22 शहर शामिल हो गए हैं और कई जगहों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। यह केवल मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि बदलते पर्यावरण और अव्यवस्थित विकास की गंभीर चेतावनी है। आने वाले तीन दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हमारे शहर रेगिस्तानी देशों से भी ज्यादा गर्म हो गए रहे हैं। इस मौसम में तापमान का बढ़ना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन यह जिस गति से बढ़ रहा है और जिस तरह से प्रभावित कर रहा है, वह परेशान करने वाला है। पहले भीषण गर्मी यानी मौसम में लू की आवर्ति दो बार हो होती थी, अब चार बार हो रही है। इस बार मानसून भी कमजोर रहने के संकेत हैं। प्रशांत महासागर के ऊपर बन रहा अलनीनो इसके लिए जिम्मेदार है। इस बार तो यहां तक भी घोषणा की जा रही है कि 1888 जैसा भयंकर सूखा पड़ सकता है। हालांकि उस समय की तुलना में आज हम बेहतर रूप से तैयार हैं। हमारे पास खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति तो नहीं है कि लोगों को भ्रम गंवानी पड़े, लेकिन देश का औद्योगिक विकास और उत्पादन ठप हो सकता है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि अब केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी तपने लगी हैं। 35 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहना इस बात का संकेत है कि धरती की प्राकृतिक संतुलन व्यवस्था तेजी से बिगड़ रही है। जब रात में भी शरीर और वातावरण को ठंडक नहीं मिलती, तब हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने कुछ राहत भरे कदम उठाए हैं। बिहार में छोटे बच्चों के स्कूल बंद किए गए हैं और पंजाब ने स्कूलों व सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया है। दरअसल, भीषण गर्मी का सबसे बड़ा कारण लगातार घटते जंगल, कंक्रीट के बढ़ते शहर, जलस्रोतों का अतिक्रमण और प्रदूषण हैं। विकास की अंधी दौड़ में हमने प्रकृति के साथ संतुलन खो दिया है। शहरों में पेड़ों की जगह सीमेंट ने ले ली और तालाबों की जगह इमारतों ने। नतीजा यह है कि धरती की सतह अधिक गर्मी सोख रही है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्मी के साथ-साथ पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। पीने, नहाने और घरेलू उपयोग में पानी की मांग बढ़ती है, जबकि भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में पानी बचाना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता बन चुका है। घरों में वर्षा जल संचयन, पानी का सीमित उपयोग और रिसाव रोकने जैसे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जलवायु परिवर्तन कई अन्य कारकों को भी जनक बन रहा है। गर्मी व कम बारिश के बाद भी भीषण सर्दी और अतिवृष्टि भी इसकी जिम्मेदार है। जैसे-जैसे यह संकट बढ़ेगा, वैसे-वैसे हालात खराब होंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर होकर काम किया जाए। सरकारों को भी समय रहते चेत जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरा तरह से मानव के नियंत्रक का सवाल है। व्यक्ति को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन का कारक हो और उन पर जोर देना चाहिए जिससे पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। यदि अभी भी चेतने में देर हुई, तो आने वाले वर्षों में यह गर्मी केवल असुविधा नहीं, बल्कि बड़े मानवीय संकट का रूप ले सकती है।

प्रतीक

डॉ. घनश्याम बादल



उभरना राजनीति में ‘काँकरोचों’ का !

सियासत में समय-समय पर ऐसे प्रतीक उभरते रहे हैं, जो शब्द मात्र नहीं, जनभावनाओं के विस्फोट का माध्यम बने हैं। कभी आम आदमी का पार्टी का गठन भी इसी तरीके से हुआ था, जैसे हाल के दिनों में विभिन्न आभासी मीडिया मंचों पर चर्चित “काँकरोच जनता पार्टी” बनी है। अभिजीत दीपके द्वारा गठित काँकरोच जनता पार्टी ऐसा ही एक राजनीतिक-सामाजिक प्रतीक बनकर सामने आई है। काँकरोच जनता पार्टी जैसा नाम भले ही व्यंग्यात्मक लगे, किंतु इसके पीछे छिपी चचेनी, अस्वतंत्र और व्यवस्था-विरोधी मनोवृति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह केवल एक डिजिटल मजाक नहीं, बल्कि उस पीढ़ी का आक्रोश माना जाना चाहिए जो स्वयं को व्यवस्था द्वारा उपेक्षित, अपमानित और अनसुना महसूस कर रही है। इस पूरी कहानी की शुरुआत उस विवादस्पद टिप्पणी से मानी जा रही है, जिसमें बेरोजगार युवाओं की तुलना “काँकरोच” से करने वाला विवाहित बयान भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से जुड़ा बताया गया है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक ‘फ्री वोलेंस’ यानी तुच्छ समझे जाने वाले प्रकरण की सुनवाई के दौरान सामने आई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मौखिक टिप्पणी में कहा गया था कि कुछ बेरोजगार युवा “काँकरोच की तरह” विभिन्न क्षेत्रों में घुस जाते हैं, जिनमें पत्रकारिता और आरटीआई एक्टिविज्म का भी उल्लेख किया गया। इस कथन के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे पूरे बेरोजगार वर्ग का अपमान माना। हालांकि अगले ही दिन जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को “गलत तरीके से पेश” किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आशय समूची युवा पीढ़ी से नहीं था, बल्कि उन लोगों से था जो “फर्जी और नकली डिग्रियों” के सहारे पेशों में प्रवेश करते हैं। इसी कथित टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक प्रतिरोध के रूप में “काँकरोच जनता पार्टी” का उदय हुआ।

शुरुआत में इसे केवल एक मीम या इंटरनेट ट्रेंड माना गया, किंतु कुछ ही दिनों में यह डिजिटल आंदोलन का रूप लेने लगा। इतना स्पष्ट है कि युवाओं ने इसे अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में इस घटना को समझें तो आज का युवा पारंपरिक राजनीति से ऊब चुका है। वह लंबी वैचारिक बहसों से अधिक प्रत्यक्ष अनुभवों पर विश्वास करता है। बेरोजगारी, परीक्षा-पत्र लीक, अवसरों की कमी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आर्थिक व सामाजिक तथा व्यक्तिगत असुरक्षा ने उसके भीतर गहरी निराशा व एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। उसे लगता है कि सत्ता, न्याय व्यवस्था या राजनीतिक दल उसकी पीड़ा को समझने के बजाय उसका उपहास कर रहे हैं, तब व्यंग्य उसका प्रतिरोध का हथियार बन सामने आता है। “काँकरोच जनता पार्टी” इसी व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति की उपज है। यह उस पीढ़ी की सोच है जो आज कह रही है कि यदि व्यवस्था हमें “काँकरोच” समझती है, तो हम उसी शब्द को प्रतिरोध के प्रतीक में बदल देंगे। पहले राजनीतिक दल जमीन से उठते थे, फिर मीडिया तक पहुंचते थे। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले पहचान बनती है और बाद में वास्तविक राजनीतिक संभावना तैयार होती है। यही कारण है कि “काँकरोच जनता पार्टी” का नाम सुनते ही लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह वायरल हो गया। हालांकि इस पूरे आंदोलन को लेकर कई प्रश्न भी हैं। क्या यह वास्तविक राजनीतिक संगठन है अथवा केवल डिजिटल असंतोष का बुलबुला मात्र है? क्या इसके पीछे कोई संगठित राजनीतिक रणनीति है? क्या यह किसी दल विशेष के विरोध या समर्थन का अप्रत्यक्ष माध्यम है? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर अभी उपलब्ध नहीं हैं। याद रहना चाहिए कि लोकतंत्र में व्यंग्य हमेशा जनभावनाओं का संकेतक रहा है। जब जनता सीधे विरोध करने में असहज महसूस करती है, तब हास्य और कटाक्ष उसकी भाषा बन जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के आंदोलनों का उदय लोकतंत्र के स्वास्थ्य का संकेत भी है और चेतावनी भी। यदि मुख्यधारा की राजनीति युवा वर्ग की पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेगी, तो असंतोष व्यंग्य, कटाक्ष और अराजक डिजिटल अभियानों में परिवर्तित होता जाएगा इसकी प्रबल संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहनशीलता और आत्मसुधार की क्षमता रही है। इसलिए सत्ता, विपक्ष, न्यायपालिका और समाज सभी को इस घटना को केवल हास्य के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान के दस्तावेज की तरह पढ़ना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)



मुद्दा

प्रमोद भार्गव

एक साथ चुनाव कराने को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्ष में सोने पर सुहागा कहावत चरितार्थ होने का तथ्य निकलकर आया है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दावा किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से सात लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। इस उपाय से देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस उपाय से देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बचे धन का उपयोग बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा,गरीब कल्याण योजनाएं और अन्य सेवाओं में किया जा सकेगा। याद रहे कि 41 सदस्यीय यह समिति एक साथ चुनाव से तमाम पहलुओं के साथ दो प्रस्तावित 129वां संविधान संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयकों के प्रारूप पर काम कर रही है। चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इन चुनाव सुधारों से देश को लाभ होना चाहिए। एक साथ चुनाव की दिशा तय करने के लिए सरकार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

समिति ने मार्च 2024 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार करते हुए चुनाव से संबंधित संशोधन विधेयक को मंजूरी भी दे दी थी। इसके प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी संसदीय समिति कर रही है। 2029 में एक देश, एक चुनाव, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ निकाय व पंचायत चुनाव भी एक साथ कराने की दिशा में केंद्र सरकार एक-एक कदम आगे बढ़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव का प्रबंध कर दिया जाएगा। साफ है, सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को क्रियान्वित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इस समय तक जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल बचा होगा, वह लोकसभा चुनाव तक ही पूरा मान लिया जाएगा। वैसे भी आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ होते रहे हैं, लेकिन 1968 और 1969 में समय के पहले ही कुछ राज्य सरकारें भंग कर दिए जाने से यह परंपरा टूट गई। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में करीब 18 संशोधन करने होंगे। इनमें से कुछ बदलावों के लिए राज्यों की अनुमति जरूरी होगी। यदि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी साथ साथ होते हैं तो फिर मतदाता सूची तैयार निर्वाचन आयोग कराएगा। इस हेतु अनुच्छेद 325 में परिवर्तन करना होगा। साथ ही अनुच्छेद 324-ए में संशोधन करते हुए निगमों और

कम खर्च में होंगे एक साथ चुनाव

एक साथ चुनाव कराने को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्ष में सोने पर सुहागा कहावत चरितार्थ होने का तथ्य निकलकर आया है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दावा किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से सात लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। इस उपाय से देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बचे धन का उपयोग बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा,गरीब कल्याण योजनाएं और अन्य सेवाओं में किया जा सकेगा। याद रहे कि 41 सदस्यीय यह समिति एक साथ चुनाव से तमाम पहलुओं के साथ दो प्रस्तावित 129वां संविधान संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयकों के प्रारूप पर काम कर रही है। चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इन चुनाव सुधारों से देश को लाभ होना चाहिए। एक साथ चुनाव की दिशा तय करने के लिए सरकार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

समिति ने मार्च 2024 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार करते हुए चुनाव से संबंधित संशोधन विधेयक को मंजूरी भी दे दी थी। इसके प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी संसदीय समिति कर रही है। 2029 में एक देश, एक चुनाव, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ निकाय व पंचायत चुनाव भी एक साथ कराने की दिशा में केंद्र सरकार एक-एक कदम आगे बढ़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव का प्रबंध कर दिया जाएगा। साफ है, सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को क्रियान्वित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इस समय तक जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल बचा होगा, वह लोकसभा चुनाव तक ही पूरा मान लिया जाएगा। वैसे भी आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ होते रहे हैं, लेकिन 1968 और 1969 में समय के पहले ही कुछ राज्य सरकारें भंग कर दिए जाने से यह परंपरा टूट गई। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में करीब 18 संशोधन करने होंगे। इनमें से कुछ बदलावों के लिए राज्यों की अनुमति जरूरी होगी। यदि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी साथ साथ होते हैं तो फिर मतदाता सूची तैयार निर्वाचन आयोग कराएगा। इस हेतु अनुच्छेद 325 में परिवर्तन करना होगा। साथ ही अनुच्छेद 324-ए में संशोधन करते हुए निगमों और

पंचायतों के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ करा लिए जाएंगे। इस संशोधन विधेयक को आधे राज्यों से भी पास करना जरूरी होगा।

इसी अनुरूप केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि 2029 तक इस कानून का लागू होना फिलहाल असंभव लग रहा है। चूंकि संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग इकाइयां हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में समानांतर किंतु भिन्न-भिन्न अनुच्छेद हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके चुनाव



प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर होने चाहिए। लोकसभा या विधानसभा जिस दिन से गठित होती है, उसी दिन से पांच साल के कार्यकाल की गिनती शुरू हो जाती है। इस लिहाज से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए कम से कम 18 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना जरूरी होगा।

विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग तक इस मुद्दे के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। यदि विपक्षी दल सहमत हो जाते हैं तो दो तिहाई बहुमत से होने वाले ये संशोधन कठिन कार्य नहीं है। यदि संसद के अन्य विपक्षी दल, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशहित में निर्णय लें तो यह विधेयक आसानी से दोनों सदनों से पारित हो जाएगा। अनेक असमानताओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बंधा है। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्र को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देती है, जिससे भिन्न स्वभाव वाली राजनीतिक शक्तियों को केंद्रीय व प्रांतीय सत्ताओं में भागीदारी का अवसर मिलता है। नतीजतन लोकतांत्रिक प्रक्रिया गतिशील रहती है, जो

देश की अखंडता व संप्रभुता के प्रति जवाबदेह है। देश में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी है। गोया, यदि बार-बार चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो मनुष्य का ध्यान बंटता है और समय व पूंजी का क्षरण होता है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रशासनिक स्थितिलता दो-ढाई महीने तक बनी रहती है, फलतः विकास कार्य और जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। एक साथ चुनाव के चलते सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षाबलों को बार-बार चुनाव द्यूटी के मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। एक साथ चुनाव के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश प्रत्येक छह माह बाद चुनावी मोड़ में आ जाता है, लिहाजा सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में तो अड़चन आती ही है, दूसरे नीतियों को कानूनी रूप देने में अतिरिक्त विलंब भी होता है। यह तर्क अपनी जगह जायज है।

वैसे भी राजनीतिक दलों की महत्ता तभी है, जब वे नीतिगत फैसलों को अधिकतम लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने सुझाव दें व उन्हें विधेयक के प्रारूप का हिस्सा बनाने के लिए नैतिक दबाव बनाएं। केंद्रीय विधि आयोग ने 2018 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि पांच साल के भीतर यदि सरकार के भंग होने की स्थिति बने तो ‘रचनात्मक अविश्वास’ मत हासिल किया जाए। मसलन, किसी सरकार को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य अविश्वास मत से गिरा सकते हैं, तो इसके विरुद्ध में जिस दल या गठबंधन पर विश्वास हो या जिसे विश्वास मत हासिल हो जाए, उसे बतौर नई सरकार की शपथ दिला दी जाए।’ बार-बार चुनाव की स्थितियां निर्मित होने के कारण सत्ताधारी राजनीतिक दल को भी यह भय बना रहता है कि उससे कहीं कोई ऐसा नीतिगत फैसला न हो जाए कि दल के समर्थक मतदाता नाराज हो जाएं। लिहाजा सरकारों को लोक-लुभान व फैसले लेने पड़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, स्वीडन, बेलजियम, दक्षिण अफ्रीका और फिलिपिंस ऐसे देश हैं, जहां एक साथ चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। गोया, भारत में भी यदि एक साथ चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ होती है तो केंद्र व राज्य सरकारें बिना किसी दबाव के देश व लोक हित में फैसले ले सकेंगी। सरकारों को पूरे पांच साल विकास व सुशासन को सुचारू रूप से लागू करने का अवसर मिलेगा। अतएव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सांसदों को देश हित में आत्म-निर्णय लेने की जरूरत है, क् योंकि इस विधि से धन की भी बड़ी बचत होगी।

(लेखक करीब पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoom@gmail.com पर दे सकते हैं।

अहंकार ही अज्ञान है



संकलित

दर्शन

सूर्य वैसे तो सारे संसार को प्रकाश और ताप देता है, पर यदि वह मेघ से आच्छन्न हो जाए तो ऐसा नहीं कर पाता। इसी भांति जब तक हृदय अहंकार के आवरण से आच्छादित रहता है, तब तक उसमें भगवान प्रकाशित नहीं हो पाते। यह अहं मेघ की तरह है। इसी के कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। यदि श्रीगुरु की कृपा से अहं-बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के पूर्ण दर्शन हो जाते हैं। जैसे, सिर्फ ढाई हाथ की दूरी पर ही साक्षात पूर्णब्रह्म श्रीरामचंद्र जी हैं, किंतु बीच में सीता रूपिणी माया का आवरण होने के कारण लक्ष्मण जी रूपी जीव को ईश्वर राम के दर्शन नहीं होते। जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार सब आवरण का मूल है। मैं के मरने पर ही सारा जंजाल दूर होगा। अगर किसी को ईश्वर की कृपा से मैं कहीं नहीं हूं- यह ज्ञान हो जाए, तब तो वह जीवनमुक्त ही हो गया। फिर उसे किसी बात का भय नहीं। अगर मैं अपने को इस अंगोछे की ओट में कर लूं तो तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक ही हूं। इसी भांति और सभी चीजों को अपेक्षा ईश्वर ही तुम्हारे सबसे ज्यादा निकट है, किंतु अहं रूपी आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं कर सकते। जब तक अहंकार रहता है, तब तक न ज्ञान होता है, न मुक्ति मिलती है। हांडी में रखे पानी और चावल, दाल, आलू आदि को तब तक छुआ जा सकता है, जब तक हांडी आग पर नहीं रखी जाती। जीव की देह मानो हांडी है और धन, मान, विद्या, बुद्धि, जाति, कुल आदि मानों दाल, चावल, आलू की तरह हैं।



संकलित

प्रेरणा

अंतर्मन



आज की पाती

ऊर्जा कांति की नई पारदर्शी शुरुआत

दुनिया तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है और इसी दिशा में सिगापुर की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसी अल्ट्रा-थिन सॉलर सेल विकसित की है, जो आने वाले वर्षों में ऊर्जा उत्पादन की पूरी तस्वीर बदल सकती है। यह तकनीक इतनी पतली है कि इनका के बाल के 10,000वें हिस्से जितनी मोटाई में भी बिजली पैदा कर सकती है। खास बात यह है कि यह सॉलर सेल पारदर्शी और रंगहीन है, इसलिए इसे खिड़कियों, कारों की विंडशील्ड, मोबाइल स्क्रीन, स्मार्ट ग्लास और ऊंची इमारतों के कांच पर आसानी से लगाया जा सकता है। अब तक सॉलर ऊर्जा का मतलब बड़े और भारी पैनल माने जाते थे, जिन्हें छतों पर लगाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है। नई तकनीक ‘बिल्डिंग इंटिग्रेटेड फोटोवोल्टिक’ अवधारणा को नई गति दे सकती है।

- मानमंद गुलिया, बहादुरगढ़

करंट अफेयर

पाक-चीन संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण, जारी होगा स्मारक सिक्का

पाकिस्तान ने चीन के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 पाकिस्तानी रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के दो साल से भी कम समय में 1951 में पाकिस्तान और चीन ने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। पाकिस्तान पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बुधस्पातिवार को घोषणा की कि यह स्मारक सिक्का 25 मई से देश भर में स्थित उसके बैंकिंग काउंटरो के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पाकिस्तान और चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, पाकिस्तान सरकार ने 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी करने का निर्णय लिया है। यह सिक्का 25 मई, 2026 से एसबीपी बैंकिंग के काउंटरो के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध होगा।’’ पाकिस्तान और चीन को व्यापक रूप से ‘‘सदाबहार सहयोगी’’ के रूप में वर्णित किया जाता है, और दोनों देशों के बीच दफ्तरों से रक्षा, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कूटनीतिक मामलों में घनिष्ठ सहयोग है।



ईधन से मिलने वाली केवल वही चीज महत्वपूर्ण है जो जलने पर ऊर्जा के रूप में निकलती है। वास्तव में, लगभग 15–20 प्रतिशत जीवाश्म ईधन कभी जलाया ही नहीं जाता। यह आधुनिक जीवन की भौतिक संरचना में बदल जाता है: प्लास्टिक, पॉलीमर, उर्वरक, चिपकने वाले पदार्थ, सॉल्वेंट और सिंथेटिक वस्त्र। जब ये उत्पाद जलाए, अपघटित किए या त्यागे जाते हैं, तो उनका कार्बन वातावरण में लौटता है, जो वैश्विक गर्मी में योगदान देता है। यह योगदान वास्तविक है, बढ़ रहा है, और अधिकांश मुख्यधारा के नेट-जीरो लेखांकन में लगभग पूरी तरह अनुरिथित है।



संकलित

प्रेरणा

आज की पाती

ऊर्जा कांति की नई पारदर्शी शुरुआत
दुनिया तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है और इसी दिशा में सिगापुर की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसी अल्ट्रा-थिन सॉलर सेल विकसित की है, जो आने वाले वर्षों में ऊर्जा उत्पादन की पूरी तस्वीर बदल सकती है। यह तकनीक इतनी पतली है कि इनका के बाल के 10,000वें हिस्से जितनी मोटाई में भी बिजली पैदा कर सकती है। खास बात यह है कि यह सॉलर सेल पारदर्शी और रंगहीन है, इसलिए इसे खिड़कियों, कारों की विंडशील्ड, मोबाइल स्क्रीन, स्मार्ट ग्लास और ऊंची इमारतों के कांच पर आसानी से लगाया जा सकता है। अब तक सॉलर ऊर्जा का मतलब बड़े और भारी पैनल माने जाते थे, जिन्हें छतों पर लगाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए होती है। नई तकनीक ‘बिल्डिंग इंटिग्रेटेड फोटोवोल्टिक’ अवधारणा को नई गति दे सकती है।

- मानमंद गुलिया, बहादुरगढ़

ऑफ बीट

सब कुछ कार्बनमुक्त करना असंभव है, लेकिन क्यों

किसी भी सुपरमार्केट में कदम रखते ही आप चारों ओर कार्बन से घिरे होते हैं। यह वह कार्बन नहीं है जिसे जलवायु रिपोर्टों में पीपीएम यानी ‘पाट्स’ पर मिलियन ‘ में मापा जाता है, बल्कि यह कार्बन का सबसे टोस रूप है। शैम्पू की बोतल की पॉलीमर परत, छत की टाइलों के पीछे की इन्सुलेशन, और आपके बैग में प्रयुक्त सिंथेटिक फाइबर... कार्बन ही तो है। ये वस्तुएं जीवमय ईंधन युग की अनजानी उपज नहीं हैं। ये इसके दूसरे चरण का हिस्सा हैं, जो जलने जितना स्पष्ट नहीं है लेकिन उनका ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक नेट-जीरो वर्ग लगभग पूरी तरह ऊर्जा तक ही सीमित रही है। यह दृष्टिकोण आवश्यक है, लेकिन इसके पीछे एक

ईधन से मिलने वाली केवल वही चीज महत्वपूर्ण है जो जलने पर ऊर्जा के रूप में निकलती है। वास्तव में, लगभग 15–20 प्रतिशत जीवाश्म ईधन कभी जलाया ही नहीं जाता। यह आधुनिक जीवन की भौतिक संरचना में बदल जाता है: प्लास्टिक, पॉलीमर, उर्वरक, चिपकने वाले पदार्थ, सॉल्वेंट और सिंथेटिक वस्त्र। जब ये उत्पाद जलाए, अपघटित किए या त्यागे जाते हैं, तो उनका कार्बन वातावरण में लौटता है, जो वैश्विक गर्मी में योगदान देता है। यह योगदान वास्तविक है, बढ़ रहा है, और अधिकांश मुख्यधारा के नेट-जीरो लेखांकन में लगभग पूरी तरह अनुरिथित है।

ट्रेंड

छात्रों का भविष्य

जब मोदी जी इटली ने मित्राइया बांदते हुए रील बना रहे थे, तब माऊत ने पीएल लीक से परेशान युवा सुइयों पर उतरकर ब्रह्मा की मांग कर रहे थे। क्योंकि एनईटी पीएल लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

जहरीली बयानबाजी

कांग्रेस की राजनीति अब विचारों से नहीं, बल्कि जहरीली बयानबाजी से घेरित है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध घटिया भाषा का प्रयोग करना, यह दर्शाता है कि कांग्रेस ने न केवल सत्ता खोई है, बल्कि अपने मूल्य भी खो दिए हैं।

- रमूति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री

महिला सीमा रक्षक

मिरानदेवमातरम के तहत, बीएसएफ की पहली महिला सीमा रक्षकों ने गाऊट एक्सेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर अदम्य साहस और अटूट संकल्प का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि बेटों की आकांक्षाओं से ऊंची कोई चोटी नहीं होती। आप पूरे देश का जीव है।

- नीतीश कुमार, पूर्व सीएम, बिहार

गैरजिम्मेदाराना बयान

एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने संसदीय समिति के सगस कहा है कि उन्हें एनईटी परीक्षा में पीएल लीक होने की बात पर विश्वास नहीं है। एक ओर तो एनटीए ने परीक्षा रट कर दी है, वहीं एनटीए अध्यक्ष ऐसे गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।

-अशोक महलौत, पूर्व सीएम, राजस्थान

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फ़ैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से

हरिभूमि कम्यूनिक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक देवेन्द्र सिंह द्वार हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड, दिल्ली रोड, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, नजदीक ईडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 से प्रकाशित। संपादक : डॉ. हिमांशु द्विवेदी। RNI No. 63924/1996, फोन : 9253681019-20, फैक्स : 274202, e-mail : rohtak@haribhoomi.com, rohtakharibhoomi@gmail.com

Postal Regd. No. P/RTK/38/2026-28